University in News on 28 May 2020

AMAR UJALA MY CITY Page 6

लविवि की कार्य परिषद की बैठक में योजनाओं पर लगी मुहर

विद्यार्थियों के लिए कर्मयोगी, शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन योजना होगी शुरू

माई सिटी रिपोर्टर

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए कर्मयोगी योजना शुरू की जाएगी। इससे उन्हें पढ़ाई के साथ ही काम करके कमाई का मौका मिलेगा। वहीं, शिक्षकों को शोधपत्र प्रकाशन या फिर किसी अन्य उपलब्धि पर प्रोत्साहन के तौर पर पुरस्कार राशि दी जाएगी। लविवि में बुधवार को हुई कार्य परिषद की बैठक में इन योजनाओं पर मुहर लगाई गई। इसके अलावा परीक्षा के स्वरूप पर कोई फैसला करने से पहले राज्य सरकार के निर्देश का इंतजार करने तथा नये संस्थान को मंजूरी देने समेत कई अहम मुद्दों पर भी कार्य परिषद ने मुहर लगाई।

लखनऊ विवि में कर्मयोगी योजना को पुअर ब्वॉयज फंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसमें काम करने की व्यवस्था नहीं थी। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम से संबंधित विभाग में काम करने का मौका मिलेगा। यह काम प्रतिदिन दो घंटे का होगा तथा प्रति घंटे उन्हें 150 रुपये का भुगतान किया जाएगा। विद्यार्थियों को अधिकतम 15 हजार रुपये तक का भुगतान किया जा सकेगा। इसी तरह शिक्षकों के

लिए प्रोत्साहन, उद्दीपन और एक्लेम योजना की शुरुआत की जा रही है। प्रोत्साहन योजना में नए शिक्षकों की सीड मनी की नूतन योजना, उद्दीपन में सर्वोत्तम शोधपत्र पुरस्कार योजना और एक्लेम में शिक्षकों को उनकी उपलब्धि पर सम्मानित करने की परंपरा शुरू की जाएगी। साथ ही कार्य परिषद ने सेवानिवृत्त शिक्षकों की मेधा का लाभ उठाने के लिए प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस की योजना भी शुरू करेगा। बैठक कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय की अध्यक्षता में हुई। इसमें कार्य परिषद सदस्य तथा कुलसचिव डॉ. विनोद कुमार सिंह उपस्थित रहे। कार्य परिषद ने विभिन्न कॉलेजों की स्थायी और अस्थायी मान्यता, शिक्षकों के अवकाश आदि के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।

परीक्षा पर सरकार के निर्देश का इंतजार

लविवि कार्य परिषद की बैठक में परीक्षा के स्वरूप पर भी चर्चा हुई। विवि प्रशासन ने किसी भी प्रकार की परीक्षा के लिए तैयार होने की बात कही, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार का फैसला राज्य सरकार के निर्देश के बाद करने पर सहमति बनी। राज्य सरकार ने ऑनलाइन तथा बहुविकल्पीय आधारित परीक्षा समेत कई विकल्पों पर विचार किया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

चार करोड़ से बनेगा नया संस्थान

लविवि में बायोकेमिस्ट्री विभाग में चार करोड़ रुपये की लागत से इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मॉलेक्यूलर्स जेनेटिक्स एंड इंफेक्शन्स डिसीजेस के नाम से नया संस्थान शुरू होगा। इसके लिए राज्य सरकार आर्थिक सहायता देगा। कार्य परिषद ने इसकी सैद्धांतिक मंजूरी दी। अनुदान आने पर इसका काम शुरू होगा।

DAINIK JAGRAN Page 5

लविवि शुरू करेगा कर्मयोगी योजना

जागरण संवाददाता, लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय नए सत्र से अपने शिक्षकों और अपने छात्रों के लिए इंटरनल क्वालिटी एशोरेंस सेल और अधिष्ठाता छात्र कल्याण के अंतर्गत नई योजनाएं शुरू करने जा रहा है। इसके अंतर्गत कार्यरत अध्यापकों के प्रोत्साहन (नए शिक्षकों के लिए सीड मनी की नई योजना)/(सर्वोत्तम शोध पत्र अवॉर्ड) जैसी योजनाओं की शुरुआत की गई है। साथ ही सेवानिवृत्त अध्यापकों की मेधा का लाभ विवि उठा सके, इसके लिए प्रोफेसर ऑफ़एमिनेंस की स्कीम भी विवि शुरू करने जा रहा है। इसके अलावा छात्रों के लिए भी नई योजनाएं भी शुरू की गई हैं। कर्मयोगी योजना के अंतर्गत चयनित छात्रों को प्रति शैक्षणिक सत्र में अधिकतम 15 हजार रुपये की धनराशि दी जाएगी। यह निर्णय बुधवार को आयोजित कार्यपरिषद की बैठक में लिया गया है। योजना के तहत लविवि से

- कर्मयोगी योजना के तहत दिन में दो घंटे व वर्ष में 50 दिन लविवि देगा काम, हर घंटे का 150 रुपये की दर से होगा भुगतान
- हर उस विद्यार्थी को काम करने के लिए दिए जाएंगे पैसे जो विवि से किसी भी तरह का कर रहा होगा प्रोफेशनल कोर्स

हर उस विद्यार्थी को काम करने के लिए पैसा दिया जाएगा जो विवि से किसी भी तरह का प्रोफेशनल कोर्स कर रहा होगा। इसके लिए लविवि ने यह नियम बनाया है कि एक छात्र को दिन में दो घंटे व वर्ष में 50 दिन काम करने का मौका मिलेगा। इसके एवज में प्रति घंटा उन्हें 150 रुपय मिलेंगे। साथ ही बीएड कॉलेजों की मान्यता को भी कार्य परिषद की बैठक में मंजूरी प्रदान कर दी गई।

प्रो. आरसी त्रिपाठी के मामले की होगी जांच: कार्यपरिषद की बैठक में तय हुआ की हिंदी विभाग के प्रोफेसर आरसी त्रिपाठी के फर्जी मार्कशीट प्रकरण में जांच कमेटी की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। समिति की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जन्तु विभाग के प्रो. सुनील त्रिवेदी और प्रो. सुधीर के बीच का वरिष्ठता का प्रकरण लंबे समय से चल रहा है। प्रकरण को निस्तारण के लिए राजभवन भेजने का निर्णय लिया गया है।

NBT Page 4

कार्यपरिषद की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले

परीक्षा पर फैसला नहीं

■ **एनबीटी, लखनऊ:** एलयू में बुधवार को कार्यपरिषद की बैठक हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। हालांकि एलयू, परीक्षाओं को लेकर कोई भी निर्णय नहीं ले सका। ऐसे में लाखों विद्यार्थी उलझन में हैं। विश्वविद्यालय में एक नए इंस्टिट्यूट की भी स्थापना होनी है, जिसके लिए एलयू को करोड़ों रुपये की आवश्यकता है। इस पर भी चर्चा हुई। समिति की बैठक में नियुक्तियों और सिनियॉरटी पद को लेकर सदस्यों की ओर काफी आपत्तियां दर्ज हुईं है। इसमें से कई मामले राजभवन को निस्तारण करने के लिए भेजे गए हैं।

सरकार के दिशा निर्देश पर एग्जाम पर फैसला

कार्यपरिषद में सत्र 2020 में होने वाली परीक्षाओं को लेकर फिलहाल कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। समिति ने परीक्षा को लेकर न तो किसी निश्चित तिथि पर विचार किया है न ही परीक्षा कैसे होंगी, कितने घंटे की होंगी इस पर कोई विचार किया गया है। समिति के निर्णय के मुताबिक सरकार के जो भी दिशा निर्देश होंगे उसी के आधार पर परीक्षाएं होंगी।

राजभवन के आदेश पर सदस्यों ने जताई आपत्ति

बीते दिनों राजभवन ने प्रो. मधुरिमा लाल और प्रो. माहेश्वरी के बीच वरिष्ठता के विवाद पर फैसला किया था। उस पर समिति के सदस्य प्रो. अनिल सिंह और प्रो. विभूति राय ने आपत्ति दर्ज करवाई है। सदस्यों का कहना है कि जब विश्वविद्यालय में सीनियॉरिटी को लेकर एक समिति बनी हुई है, जिसमें कुलपति और दो डीन की अध्यक्षता में निर्णय लिया जाता है। जिसके बाद भी अगर किसी को आपत्ति है तो वह आगे जाकर अपनी बात रखता, लेकिन विश्वविद्यालय में तो नियम के खिलाफ ही कार्रवाई की गई और सीधा राजभवन के आदेश पर फैसला सुना दिया गया। समिति के सदस्यों का कहना था कि ये विश्वविद्यालय के नियमों की अवहेलना है। वहीं, विवि के कम्प्यूटर साइंस के प्रो. ब्रजेंद्र सिंह के सीनियॉरिटी पद की भी जांच होगी, जिसे लेकर कुलपति ने तीन माह में समिति से पुनः कार्रवाई करते हुए जांच करने को कहा है।

चार से छह करोड़ में खुलेगा इंस्टिट्यूट

इंस्टिट्यूट ऑफ अडवांस मालिकुलर जेनेटिक ऐंड इंफेक्शन डिजीज खोलने के लिए मेडिकल कॉउंसिल ऑफ इंडिया(एमसीआई) से अनुमति लेनी की जरूरत पड़ेगी। साथ ही इंस्टिट्यूट खोलने के लिए करीब चार से छह करोड़ रुपये की विश्वविद्यालय को आवश्यकता पड़ेगी, जिस पर समिति ने तय किया है कि अगर सरकार से अनुदान मिलेगा तो ही इंस्टिट्यूट की स्थापना हो सकेगी। वहीं शिक्षकों की नियुक्ति पर भी चर्चा की गई इसके तहत अब एलयू और एलयू के सम्बद्ध कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति न्यूनतम वेतन 21 हजार 600 रुपये पर ही होगी।

एलयू में दोबारा पढ़ा सकेंगे सेवानिवृत्त शिक्षक

- एलयू की कार्यपरिषद की बैठक में आईक्यूएसी की चार योजनाओं पर मुहर
- बैठक में अन्य कई मामलों पर भी हुई चर्चा

■ एनबीटी, लखनऊ

लखनऊ विश्वविद्यालय (एलयू) के सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों को दोबारा पढ़ाने का मौका मिलेगा। 'प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस' योजना के तहत एक समिति बनाई जाएगी, जो शिक्षकों को उनके अनुभव और शोध कार्य के आधार पर चयन करेगी। एलयू में बुधवार को हुई कार्यपरिषद की बैठक में इंटरनल क्वॉलिटी ऐश्योरेंस सेल (आईक्यूएसी) की इस योजना पर मुहर लगा दी गई। इसके अलावा शिक्षकों की अन्य तीन प्रोत्साहन, उद्दीपन और एक्लेम योजनाओं को भी मंजूरी दी गई।

एलयू प्रवक्ता दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि आईक्यूएसी के अंतर्गत शिक्षकों को काम के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए ये योजनाएं बनाई गईं हैं। प्रोत्साहन, उद्दीपन और एक्लेम का लाभ नए असोसिएट और असिस्टेंट प्रेफेसर पद पर तैनात शिक्षकों को ही मिलेगा।

जन्तु विभाग शिक्षकों का विवाद पहुंचा राजभवन

एलयू के जन्तु विभाग के प्रो. सुनील त्रिवेदी और प्रो. सुधीर कुमार के बीच का सीनियॉरटी का मामला लंबे समय से एलयू में लंबित चला आ रहा था। बैठक में तय हुआ कि इस मामले को निस्तारण के लिए राजभवन भेजा जाएगा।

फर्जी मार्कशीट मामले में बनेगी समिति

बैठक में यह भी तय हुआ कि पत्रकारिता विभाग के प्रो. आरसी त्रिपाठी के फर्जी मार्कशीट मामले में इंक्वॉयरी कमिटी की रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए समिति बनाई जाएगी, जो आगे की कार्यवाही करेगी। समिति में किसे शामिल किया जाएगा, फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

छात्र हित में शुरू होगी 'कर्मयोगी योजना'

कार्यपरिषद की बैठक में छात्रों हित के लिए शुरु होने वाली 'कर्मयोगी योजना' को भी मंजूरी मिल गई है। इसके तहत एलयू से प्रफेशनल कोर्स कर रहे हर स्टूडेंट को दिन में दो घंटे और साल में 50 दिन काम करने का मौका मिलेगा। इसके लिए एलयू प्रशासन प्रति घंटे 150 रुपये भी देगा।

i-Next Page 4

'कर्मयोगी' स्टूडेंट्स को एलयू से 15 हजार

एलयू की कार्य परिषद में लिए गए कई निर्णय

lucknow@inext.co.in

LUCKNOW(27 May): एलयू नए सत्र से अपने शिक्षकों और छात्रों के लिए इंटरनल क्वॉलिटी एशोरेंस सेल और अधिष्ठाता छात्र कल्याण के अंतर्गत नयी योजनायें शुरू करेगा. कर्मयोगी योजना के अंतर्गत चुने स्टूडेंट्स को प्रति सत्र अधिकतम 15 हजार रुपए दिए जाएंगे. यह निर्णय बुधवार को वीसी प्रो. आलोक कुमार राय की अध्यक्षता में आयोजित कार्यपरिषद की बैठक में लिया गया.

दिन में दो घंटे काम

कर्मयोगी योजना के तहत हर उस स्टूडेंट को काम करने का पैसा दिया जाएगा जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहा होगा. इसके लिए स्टूडेंट को दिन में दो घंटे व साल में 50 दिन काम करने का मौका मिलेगा. इस एवज में प्रति घंट 150 रुपये एलयू प्रशासन की ओर से दिए जाएंगे. बीएड कॉलेजों की मान्यता को भी कार्य परिषद की बैठक में मंजूरी प्रदान कर दी गई.

CONCEPT PIC

प्रो. त्रिपाठी मामले की होगी जांच

कार्यपरिषद की बैठक में तय हुआ की हिंदी विभाग के प्रोफेसर आरसी त्रिपाठी के फर्जी मार्कशीट प्रकरण में जांच कमेटी की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी. समीति की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. एलयू के जन्तु विभाग के प्रो. सुनील त्रिवेदी और प्रो. सुधीर कुमार के बीच वरिष्ठता का प्रकरण चल रहा है. प्रकरण को निस्तारण के लिए राजभवन भेजने का निर्णय किया गया है. समिति ने एग्जाम को लेकर न तो डेट पर विचार किया है, न ही एग्जाम कैसे होगा इस पर कोई विचार किया. सरकार के जो भी दिशा निर्देश होंगे उसी के आधार पर एग्जाम होंगे.

न्यूनतम वेतन पर नियुक्ति

बैठक में सभी सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में तैनात शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का प्रस्ताव भी रखा गया. जिस पर परिषद ने अपनी मुहर लगा दी. जिसके अनुसार अब एलयू व उससे संबद्ध सेल्फफाइनेंस कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति न्यूनतम वेतन 21,600 रुपये पर ही हो.

राजभवन के आदेश पर आपत्ति

बीते दिनों राजभवन ने प्रो. मधुरिमा लाल और प्रो. महेश्वरी के बीच वरिष्ठता के विवाद को लेकर जो निर्णय लिया है, उस पर समिति के सदस्यों ने आपत्ति दर्ज करवाई है.

जेनेटिक इंस्टीट्यूट के लिए 6 करोड़

कार्य परिषद की बैठक में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मालिकुलर जेनेटिक एंड इंफेक्शन डिजीज खोलने का प्रस्ताव रखा गया. इंस्टीट्यूट खोलने के लिए लगभग चार से छह करोड़ रुपए की को आवश्यकता होगी. जिस पर समिति ने तय किया है कि अगर सरकार से इंस्टीट्यूट खोलने के लिए अनुदान मिलेगा तो ही इंस्टीट्यूट की स्थापना हो सकेगी.

वीसी की अध्यक्षता में हुई बैठक.

एलयू में दो शिफ्ट में क्लास लगाकर कराएंगे पढ़ाई!

हालात देखते हुए एलयू व संबद्ध कॉलेज रणनीति बनाने में जुटे

LUCKNOW (27 May inext): एग्जाम व नए सत्र को लेकर शैक्षिक संस्थान मंथन कर रहे हैं. एलयू में भी लगातार शैक्षणिक सत्र को लेकर रणनीतियां बनाई जा रही हैं. एलयू के अधिकारियों के मुताबिक जब यूनिवर्सिटी खुलेगी तो कोरोना से बचाव के लिए यहां कई बड़े बदलाव किए जाएंगे. सभी विभागों के टाइम टेबल को पूरी तरह से रीशेड्यूल कर क्लासेस ऐसे अरेंज की जाएंगी जिससे स्टूडेंट्स की कैंपस में संख्या ज्यादा न हो.

सोशल डिस्टेंसिंग पर फोकस

एलयू प्रवक्ता प्रो. दुर्गेश श्रीवास्तव का कहना है कि हालात को देखकर सरकार के जो भी निर्देश होंगे उसी के तहत आगे की योजना बनाई जाएंगी. वहीं एलयू के अधिकारियों के मुताबिक एग्जाम को लेकर रणनीति तैयार की जा चुकी है केवल सरकार के निर्देश को देखते हुए तिथियों में फेरबदल करना पड़ेगा. अधिकारियों के मुताबिक अगले कुछ महीनों में दो पालियों में क्लास संचालित की जाएगी जिसमें कोर्स पूरा करने के लिए एक ही विषय की क्लास दिन में दो बार भी कराई जा सकती है.

एलयू की तरह ही क्लास

वही एलयू क्लासेस संचालित करने के लिए स्पेशल टाइम टेबल बनाने की तैयारी कर रहा है. ठीक उसी तरह कॉलेजों को भी कोर्स पूरा कराने के लिए स्पेशल टाइम टेबल बनाना होगा. जिस विषय का कोर्स सबसे ज्यादा पीछे होगा उसमें दो शिफ्टों में पढ़ाई कराकर उसे पूरा कराना होगा.

Hindustan Page 7

कर्मयोगी छात्र को हर साल 15 हजार कमाने का मौका

लखनऊ | **वरिष्ठ संवाददाता**

लविवि छात्रों और शिक्षकों के लिए नए सत्र में नई योजनाएं लेकर आ रहा है। विवि कार्यपरिषद की बैठक में बुधवार को इन पर मुहर लगाई गई।

विवि ने कर्मयोगी योजना के तहत छात्र को एक शैक्षिक सत्र में 15 हजार तक कमाने का अवसर देने का फैसला लिया है। 'कर्मयोगी योजना' में छात्र को विवि के साथ जुड़कर काम करने का मौका मिलेगा। एलयू ने नियम यह बनाया है कि एक छात्र को दिन में दो घंटे व साल में 50 दिन काम करने का मौका मिलेगा। इसके लिए प्रति घंटे के हिसाब से लविवि 150 रुपए भुगतान करेगा। बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय ने की। बैठक में कई बीएड कॉलेजों के सहयुक्तता विस्तार पर भी मुहर लगाई गई।

प्रवक्ता डॉ. दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि विवि नए सत्र में शिक्षकों की इंटरनल क्वालिटी एश्यारेंस सेल के अंतर्गत कार्यरत अध्यापकों के लिए प्रोत्साहन या सर्वोत्तम शोध पत्र अवॉर्ड और एक्लेम जैसी योजनाओं की शुरुआात की गई है। इसके साथ ही सेवानिवृत्त अध्यापकों की मेधा का लाभ यूनिवर्सिटी उठा सके, इसके लिए 'प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस' स्कीम भी चलाई जाएगी।

PIONEER Page 3

लविवि में छात्रों के लिए कर्मयोगी योजना

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

लखनऊ विश्वविद्यालय में कर्म योगी योजना को लागू करने पर कार्य परिषद ने अपनी हरी झंडी दे दी है। इस योजना के तहत विश्व विद्यालय की तरफ से हर उस छात्र को पैसे दिए जाएंगे जिन्होंने प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला ले रखा हो। बुधवार को विश्वविद्यालय में बुलाई गई कार्यपरिषद ने कई अहम मसलों पर अपने निर्णय दिए। इनमें सबसे प्रमुख मुद्दे के रूप में शिक्षकों की नियुक्ति का मसला शामिल रहा। अब विश्वविद्यालय सहित अनुदानित व निजी मेडिकल कॉलेजों में न्यूनतम वेतन पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक राय की अध्यक्षता में आयोजित कार्य परिषद की बैठक के दौरान कर्म योगी योजना को मंजूरी दी गई। इसके लिए विश्वविद्यालय स्तर पर नियम भी तय किए गए हैं। नियम के मुताबिक एक छात्र को दिन में 2 घंटे व साल में 50 दिन काम करने का मौका मिलेगा। जिसके एवज में विश्वविद्यालय की तरफ से प्रति घंटे 150 रुपये छात्रों को दिए जाएंगे। बैठक के दौरान शासन के निर्देश पर विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अनुदानित व निजी कॉलेजों में न्यूनतम नियुक्ति पर परिषद ने मुहर लगा दी। अब विवि से सम्बद्ध कालेजों में न्यूनतम 21600 रुपये पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। कार्यपरिषद में सत्र 2020 में होने वाली परीक्षाओं को लेकर फिलहाल के लिए कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। समिति

न्यूनतम वेतन पर नियुक्ति किए जाने पर कार्यपरिषद ने लगाई मुहर

ने परीक्षा को लेकर न तो किसी निश्चित तिथि पर विचार किया है न ही परीक्षा कैसे होंगी, कितने घण्टे की होंगी इस पर कोई विचार किया गया है। समिति के निर्णय के मुताबिक सरकार के जो भी दिशा निर्देश होंगे उसी के आधार पर परीक्षाएं होंगी। वही बैठक के दौरान बीते दिनों राजभवन की तरफसे प्रो. मधुरिमा लाल और प्रो. महेश्वरी के बीच वरिष्ठता के विवाद को लेकर लिए गए निर्णय पर समिति के सदस्य प्रो. अनिल सिंह व प्रो. विभूति राय ने आपत्ति दर्ज करवाई है। सदस्यों का कहना है कि जब विश्वविद्यालय में वरिष्ठता को लेकर एक समिति बनी हुई है, जिसमें कुलपति और दो डीन की अध्यक्षता में निर्णय लिया जाता है। इसके बाद भी अगर किसी को आपत्ति है तो वह आगे जाकर अपनी बात रखता है, लेकिन विश्वविद्यालय में तो नियम के विरूद्ध ही कार्रवाई की गई और सीधा राजभवन के आदेश पर फैसला सुना दिया गया। समिति के सदस्यों का कहना था कि यह विश्वविद्यालय के नियमों की अवहेलना है। बैठक में पत्रकारिता विभाग के प्रो. आरसी त्रिपाठी के फर्जी मार्कशीट प्रकरण में इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया गया। एलयू के जन्तु विभाग के प्रो. सुनील त्रिवेदी और प्रो. सुधीर कुमार के बीच का वरिष्ठता निर्धारण के मसले पर प्रकरण को राजभवन भेजने का निर्णय लिया गया। वहीं बैठक में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मालिकुलर जेनेटिक एंड इंफेक्शन डिजीज खोलने के मसले पर सरकारी अनुदान मिलने पर ही कदम उठाने का निर्णय लिया गया। इंस्टीट्यूट खोलने के लिए मेडिकल कॉउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमति लेनी की जरूरत पड़ेगी। ये अनुमति इसलिए लेनी होती है क्योंकि इंस्टीट्यूट में ब्लड सैंपल व अन्य कार्य होंगे। जिसके लिए एक एथिकल कमेटी की सहमति जरूरी होती है।

TOI Page 2

LU initiative to make students self-reliant

TIMES NEWS NETWORK

Lucknow: Lucknow University students will soon get an opportunity to be 'Karma Yogi' with the help of a scholarship that will give them a chance to earn while they learn.

Besides, a 'Chhatra Kalyan' scholarship will be introduced for meritorious undergraduate students.

To honour teachers for academic excellence, LU has also started three new schemes – 'Protsaahan', 'Uddipan' and 'Acclaim'.

These new initiatives, to be started in the centenary year of the university, were approved by the executive council on Wednesday.

LU vice-chancellor Prof Alok Kumar Rai said, "Under 'Karma Yogi' scholarship, a student will have the opportunity to work for the university in the area in which she/he is attaining degree, be it undergraduate or postgraduate."

"The selected students can work for two hours a day and a total of 50 hours in a year. For each hour, they will be paid Rs 150, which means an opportunity to earn Rs 15,000 in a year," he said.

The VC said earlier toppers and economically weak students were given scholarships in final year of graduation but now the university plans to reward them in all three years of graduation under the Chhatra Kalyan scholarship. Details of scholarship will released later.

"Protsaahan scheme for teachers will provide financial support for innovation and research, while award best research paper will be awarded with 'Uddipan'. 'Acclaim' will be an incentive for teachers. Details of schemes will be announced later," the VC said.